गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : दिल्ली सरकार की पहलें

मोहम्मद सुहैल और वसीम अहमद खान



शिक्षा सफल जीवन की आधारशिला है : यह शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल देकर सशक्त बनाती है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसे कहते हैं जो ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों और मूल्यों के बेहतर अधिग्रहण पर ज़ोर दे ताकि व्यक्ति को मानवीय, सामाजिक, राष्ट्रीय और सार्वभौमिक लक्ष्यों के साथ सही तरीक़े से पेश आने में मदद मिले।

स्कूलों में विकसित किए गए संज्ञानात्मक और ग़ैर-संज्ञानात्मक कौशल आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। इससे शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य व्यक्ति बनने में मदद मिलती है और साथ ही यह शान्तिपूर्ण, आनन्दपूर्ण और न्यायोचित समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर देश के संसाधन के रूप में एक कुशल मानव का विकास करना है तो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। गुणवत्ता के मानकों की दृष्टि से देखें तो वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चे असमान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उनकी सफलता पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उस स्तर से जुड़ी है जिसे वे प्राप्त कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कुशलतापूर्वक ऐसे नवाचार करने में सक्षम होता है जिनसे आर्थिक विकास उन्नत होता है।

दिल्ली के सरकारी के स्कूलों का वर्तमान परिदृश्य

दिल्ली भारत की राजधानी और एक मेट्रो शहर है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान है। दिल्ली में शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं जैसे निजी स्कूल,सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा संचालित स्कूल और शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित स्कूल। इनके अलावा कई ग़ैर-मान्यता प्राप्त स्कूल भी हैं जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं।

दिल्ली के स्कूलों में चालीस लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और उनमें से अधिकांश एमसीडी और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ते हैं। हाल के अध्ययन और सर्वेक्षणों में पाया गया है कि दुर्भाग्य से बच्चों के अधिगम का स्तर बहुत कम है : यह पाया गया कि दिल्ली में 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा अपनी मातृभाषा को धाराप्रवाह रूप से नहीं पढ़ सकते हैं और 50 प्रतिशत से अधिक या आधे विद्यार्थी भाग के सरल सवाल हल नहीं कर सकते तथा अँग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में भी अधिगम की यही स्थिति पाई गई है। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि कक्षा छह में केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थी ही हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें और दूसरी कक्षा की अँग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ सकते हैं।

अधिगम के स्तरों का यह परिदृश्य हमें दूरदराज़ के ऐसे अन्य स्थानों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, जहाँ शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना मुश्किल होता है। विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना महत्त्वपूर्ण है। यूनेस्को (2014) ने सिफ़ारिश की थी कि शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार होना चाहिए और सभी की उत्कृष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि सभी को मान्यता प्राप्त और औसत दर्जे के अधिगम परिणाम प्राप्त हों, विशेष रूप से साक्षरता, गणना और आवश्यक जीवन कौशल में।

नवाचारों की आवश्यकता

2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस महान उद्देश्य के साथ लागू किया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले (1 से 8वीं तक की कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए) और उसके लिए शिक्षा सुलभ हो। यह अधिकार केवल शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है।

विद्यार्थियों में अधिगम के स्तर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी हो जाता है कि अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ नई और अभिनव शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को अपनाया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता में नवाचार बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो सके जो प्रभावी ढंग से संवाद कर सके, आलोचनात्मक और तर्कसंगत रूप से सोच सके, सहयोग के साथ काम कर सके और अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय ले सके। इसलिए अब वक़्त आ गया है कि पाठ्यचर्या की समीक्षा की जाए और

नवीन पद्धतियों पर ज़ोर दिया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

दिल्ली सरकार द्वारा की गई पहलें

लुक बियॉन्ड बेसिक्स, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर, 2017) में बताया गया है कि 14-18 आयु वर्ग के 86 प्रतिशत युवा, चाहे वे स्कूल में हों या कॉलेज में, अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हैं और यह दावा किया गया है कि इस आयु वर्ग का लगभग 25 प्रतिशत अभी भी अपनी ही भाषा के मूल पाठों को धाराप्रवाह रूप नहीं पढ़ सकता। उनमें से केवल 43 प्रतिशत ही तीन अंकीय संख्या में एक अंकीय संख्या का सही तरीक़े से भाग देने में सक्षम हैं।

कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कठिनाइयों को दूर करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के तरीक़े खोजने की कोशिश की है। सरकार ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए।

जून 2016 में 'चुनौती' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के बीच अधिगम के अन्तराल को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना था कि कक्षा 9 में कोई ड्रॉपआउट न हो। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को दो समूहों (प्रतिभा और निष्ठा) में और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को तीन समूहों (प्रतिभा, निष्ठा और विश्वास) में, उनके सीखने के स्तर के अनुसार, विभाजित किया गया था। शिक्षकों से कहा गया कि वे पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति का पालन करने की बजाय उपयुक्त तरीक़े अपनाएँ। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए और उनके लिए विशेष सामग्री को डिज़ाइन और विकसित किया गया ताकि अधिगम के बुनियादी कौशल यानी पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणितीय क्षमता मज़बूत की जा सके।

दिल्ली सरकार की एक और पहल मेंटर शिक्षकों की नियुक्ति है। स्कूलों में शिक्षकों को ऑनसाइट शैक्षणिक और अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा निदेशालय के स्कूलों से लगभग 200 शिक्षकों का चयन किया गया है। एक मेंटर शिक्षक को हर हफ़्ते पाँच या छह स्कूलों का दौरा करना होता है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अध्यापन और शिक्षण का निरीक्षण करना होता है तथा शिक्षकों की सहायता करनी होती है।

इसके अलावा सरकार ने स्कूल में शिक्षकों की सहायता करने के लिए शिक्षक विकास समन्वयक की एक और योजना शुरू की। इन समन्वयकों का काम शिक्षकों का कौशल बढ़ाने में मदद करना, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को फीडबैक प्रदान करना, मेंटर शिक्षकों के सम्पर्क में रहकर उनके ख़ुद कौशल में सुधार करने में मदद करना आदि; और ऐसा करने के लिए वे गहन विचार-मन्थन करते और ऐसे समाधान खोजते जिनसे उनके स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद हो सके।

दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक और योजना 'मिशन बुनियाद' है, यह योजना 11 मई 2018 को शुरू हुई और 30 जून 2018 को समाप्त हुई। मूल रूप से यह योजना पहले शुरू की गई योजना का ही विस्तार है जिसे 'रीडिंग कैम्पेन' के रूप में जाना जाता है, जिसे कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के पठन कौशल से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने और सम्बोधित करने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान के लिए बुनियादी अवधारणाओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) को विकसित और संचालित किया गया था। सरकार द्वारा यह दावा किया गया कि 'रीडिंग कैम्पेन' की पहल के अच्छे परिणाम आए और लगभग 75,000 विद्यार्थियों ने धाराप्रवाह रूप से पढ़ना सीखा और 90,000 विद्यार्थियों ने बुनियादी गणितीय संक्रियाओं को हल करना सीखा। हालाँकि यह भी बताया गया है कि लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी अभी भी वांछित स्तर से नीचे हैं। इसलिए लेखन और बुनियादी संख्यात्मक क्षमता से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए मिशन बुनियाद का शुभारम्भ किया गया।

यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों जैसे 'प्रगति शृंखला' का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह 'बिना बोझ के शिक्षा' के सिद्धान्त पर आधारित है। कक्षा 6 से 8 के लिए अँग्रेज़ी, हिन्दी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए बुनियादी शिक्षण सामग्री का एक सेट विकसित किया गया था। इस सामग्री को छापकर सरकारी स्कूलों के प्रत्येक विद्यार्थी को मुफ़्त में दिया गया जिससे उनके सीखने के अनुभवों का संवर्धन हो। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन दिल्ली सरकार की एक और उल्लेखनीय पहल है। यह अभियान इस विचार पर आधारित है कि विद्यार्थियों को स्कूल के माहौल से परिचित कराया जाए और एनसीएफ़ 2005 द्वारा बताए गए अधिगम के गतिविधि-आधारित अनुभवों पर ज़ोर दिया जाए। ग्रीष्मकालीन शिविर में कला और शिल्प, पढ़ना और लिखना, खेल, नृत्य तथा संगीत जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जिनमें भाग लेकर विद्यार्थी सीख पाएँ और विभिन्न कौशल हासिल कर पाएँ।

दिल्ली सरकार की एक और पहल कला उत्सव है। इसे अन्य राज्यों के सौन्दर्यशास्त्र, विरासत, रीति-रिवाजों, संस्कृति और

परम्पराओं के बारे में विद्यार्थियों को बताने और जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह पहल शिक्षा में कला को और संगीत, रंगमंच, दृश्य कला और शिल्प के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देती है।

दिल्ली सरकार का एक और महत्त्वपूर्ण क़दम मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग्स (MPTMs) की स्थापना है। इसकी वजह से शिक्षकों और अभिभावकों को हर महीने मिलने का अवसर मिला और उनके बीच संचार सम्बन्धी अन्तराल को पाटने में मदद मिली। इसके अलावा विद्यार्थियों के अधिगम और विकास के बारे में उचित फीडबैक प्रदान करने का मौक़ा भी मिला। ऐसा होने से शिक्षक और माता-पिता के बीच सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भी विकसित होता है।

योजनाओं का SWOC विश्लेषण

योजनाओं के गुण

- सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ यह दर्शाती हैं कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के अधिगम के माहौल की बेहतरी के लिए सरकार स्पष्ट इरादा और इच्छा रखती है।
- दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का 25 प्रतिशत विद्यार्थियों और शिक्षकों के शैक्षिक वातावरण के संवर्धन और बेहतरी के लिए ख़र्च किया है।
- पूरक और उपचारात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है।
- नियमित रूप से शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित करके शिक्षकों को शैक्षिक जानकारी दी जाती है।
- शिक्षक विकास समन्वयकों द्वारा शैक्षणिक हस्तक्षेप करके फीडबैक दिया जाता है।
- विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी।
- शिक्षक इस तरह के कार्यों का लगातार समर्थन करते हैं, हालाँकि इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।

योजनाओं की कमियाँ

- विद्यार्थियों की भागीदारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है : केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में इन कक्षाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि वे गर्मियों की छुट्टियों में अपने गाँव/शहर जाना पसन्द करते हैं और ऐसी कक्षाओं में नहीं जाना चाहते हैं।
- सरकारी स्कूल पहले से ही शिक्षकों की संख्या को लेकर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 200 शिक्षकों को मेंटर शिक्षकों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है और पहले से नियुक्त शिक्षकों में से 1029 शिक्षक, शिक्षक विकास समन्वयकों के रूप में काम कर रहे हैं, इस प्रकार शिक्षकों से सम्बन्धित कठिनाई और बढ़ जाती है।
- अधिकतर अतिथि शिक्षक मिशन बुनियाद में शामिल हैं।
- शिक्षकों को कोई अतिरिक्त प्रशंसा या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जिससे प्रेरित होकर वे स्थिति में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
- सरकार वास्तविक अधिगम पर ज़ोर देने की बजाय विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षक की डायरी, जलपान के वितरण जैसी चीज़ों के आँकड़े माँगती है।

अवसर

- सरकार, स्कूल प्रशासन के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी सीखने के माहौल को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है ताकि विद्यार्थी पढ़ने, लिखने तथा बुनियादी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने पर विशेष ध्यान देते हुए बेहतर तरीक़े से सीख सकें।
- इसके अलावा ये पहलें सरकारी स्कूलों के अकादमिक वातावरण में सुधार के लिए अनुवर्ती कार्यक्रमों को लागू करने के अवसर प्रदान करती हैं।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने से शिक्षकों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपने मौजूदा ज्ञान और कौशल में सुधार करने का मौक़ा मिलता है।
- इसी तरह विद्यार्थियों को अपनी अकादमिक कमजोरियों को दूर करने का भी मौक़ा मिलता है, विशेष रूप से पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणितीय समस्याओं के सम्बन्ध में।

चुनौतियाँ

- अधिक संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रशासन के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी सबसे चुनौतीपूर्ण काम है।
- अलग-अलग कार्यक्रमों को एक के बाद एक करना और दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित पाठ्यक्रम बनाए रखना मुश्किल है।
- शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को गर्मी की चिलचिलाती धूप में आने के लिए प्रेरित करना भी एक कठिन काम है।
- ऐसी योजनाओं और पहल का वास्तविक मूल्यांकन करना एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

विगत समय में यह देखा गया है कि सरकारों ने केवल बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग प्रमुखों को धन आवंटित करने में असावधानी बरती जिसके परिणामस्वरूप प्रति बच्चे के खर्च में वृद्धि हुई लेकिन स्कूलों के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बार दिल्ली सरकार ने शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता दी है और विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए शैक्षिक अवस्था और शैक्षिक वातावरण को संवर्धित करने और बेहतर बनाने के लिए अपने बजट का बहुत बड़ा भाग ख़र्च किया है। सरकार ने समझदारी के साथ क़दम उठाया और बुनियादी ढाँचे में सुधार के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू कीं। इसने विद्यार्थियों को बिना बोझ के शिक्षा दिलाने के अवसर प्रदान किए और 'आनन्दपूर्ण शिक्षण-अधिगम' दृष्टिकोण की सहायता से उनके अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया। हालाँकि शिक्षकों और प्रशासन के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों को एक के बाद एक करना और दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित पाठ्यक्रम बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

इस सबके बावजूद शिक्षकों को इतनी ईमानदारी से काम करते देखना और ऐसे बदलावों का समर्थन करते हुए देखना बहुत उत्साहजनक है जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।

References:

1 Circular No. DE.23 (612)/ Sch. Br./ 2018/265 dated 05.03.2018 issued by DOE, GNCT of Delhi.
2 Circular No. DE.23 (632)/ Sch. Br./ 2018/443 dated 05.04.2018 issued by DOE, GNCT of Delhi.
3 Circular No. DE.23 (632)/ Sch. Br./ 2018/444 dated 05.04.2018 issued by DOE, GNCT of Delhi.
4 Key Learning Indicators of Performance (2015), The Centre for Learning Excellence, Lancashire County Council, United Kingdom.
5 Look Beyond Basics (2017), Annual Status Education Report, ASER centre, Safdarjung, New Delhi
6 Quality Education for All: Initiatives and Innovations Transforming Delhi Education, Published by Government of NCT, Delhi.
7 Quality in School Education, Quality Council of India, New Delhi.

मोहम्मद सुहैल एक शिक्षक हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से शिक्षा में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने आउटडोर शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और आईसीटी में विविध और बहुआयामी रुचि दिखाई है। उन्होंने कार्यरत शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए आउटडोर शिक्षा पर आधारित एक प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया है। उनसे *msuhall.edu@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वसीम अहमद खान शिक्षक प्रशिक्षण और ग़ैर-औपचारिक शिक्षा विभाग (IASE), शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में प्रोफ़ेसर हैं। उन्हें 30 से भी अधिक वर्षों का कार्यानुभव है और वे सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा, मार्गदर्शन व परामर्श, पर्यावरण शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन व पर्यवेक्षण, अल्पसंख्यक शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। उनसे *wak.jmi@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल